ज्यादा दूर नहीं है। हम लोगों के सम्बन्ध नेपाल के साथ मोस्ट कोर्डियल हैं।

संविधान के अनुसार वाटर स्टेट सबजैक्ट है। आपका कहना ठीक है कि काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसकी प्रेजीडेंट प्रधान मन्त्री जी हैं उसमें यह तय हुआ कि वटर कनकरेंट सवजैक्ट न बनाया जाय और स्टेट सबजैक्ट रहते हुए भी जितने चीफ मिनिस्टर्ज हैं उनको कान्फिडेंस में लेकर बात की जाए और मामले तय किए जाएं।

जहां तक बाटर रेट का सम्बन्ध है या करप्शन की बात है मैं मानता हूं करप्शन है। दो चार इंस्टैंसिस हमें आप दें और मैं स्टेट गवर्नमेंट को कहूँगा कि माननीय सदस्य ने इस तरह की शिकायत की है और आप बाजाब्ता जांच करवाएं। आप स्पैसिफिक केसिस दें और मैं जरूर उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजूंगा।

श्री राम विलास पासवान : आज पूरा देश अकाल से जल रहा है। क्या केन्द्रीय टीम बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान गई थी या नहीं ? क्या उसने अपनी रिपोर्ट दी थी या नहीं ? उसके आधार पर आपने राज्य सरकारों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी को मुफ्त देने के बारे में कहा है ?

SHRI Z. R. ANSARI : The question does not arise out of this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Revision of Forest Policy

*209. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are considering to revise the existing forest policy of the country; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The revision is yet to be finalised by the Government. A copy of the draft Forest Policy which was considered by the Central Board of Forestry in August, 1982, is laid on the Table of the House. [Placed in library. *See* No. LT-5518/82].

Reorientation of Research Programme by ICAR to give Thrust to Dry Land Farming

*213. KUMARI PUSHPA DEVI SINGH : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the Indian Council of Agricultural Research has reoriented its research programme to give a thrust to dry land agriculture as well as production of pulses and oilseeds ;

(b) if so, whether according to the new 20-Point Programme scientists have estimated that even with the existing technology it was possible to raise the production of dry land ; and

(c) if so, the steps taken by the Council to boost the production of

pulses and oilseeds and launching of a programme for the production of seeds of improved quality ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Madam. The Indian Council of Agricultural Research has reoriented its research programmes in areas of Dryland Agriculture, pulses and oilseeds production by :

(i) strengthening the existing research centres in terms of infrastructure and development of more scientists and establishing new research centres ;

(ii) increasing the total Plan outlay significantly in the Sixth Plan over actual expenditure of Fifth Plan ;

(iii) developing new programmes of research to refine available technology and develop new strategies ; and

(iv) improving transfer of technology through additional Operational Research Projects, technical publications, stepping up training programmes and increasing number of demonstrations on pulses, oilseeds and dry farming of family farms under Lab to Land Programme.

(b) Yes, Madam. With the help of existing technologies, it is possible to increase the yield in many a dryland areas by 50 to 100 per cent although the production potential of available technologies is much higher.

(c) Besides the steps mentioned under item (a), the Indian Council of Agricultural Research has released improved varieties of principal pulses and oilseeds crops grown in rainfed areas suited to the growing seasons in each region, stepped up breeder's seed production and is providing necessary technical support to the Department of Agriculture and Rural Development in their programmes.

नेपाल को चावल का निर्यात

214. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेपाल के खाद्यान्न संकट को ध्यान में रखते हुये उसे 10 हजार टन चावल देने का है;

(ख) यदि हां, तो यह चावल किस दर पर दिया जायगा;

(ग) क्या सरकार अपने देश में चावल की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क), (ख) और (घ) नेपाल सरकार ने भारत सरकार से उस देश में खाद्यान्नों की अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए चावल सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था। दोनों देशों के बीच स्थित निकट तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए और सद्भावना के रूप में भारत सरकार ने जिन्स ऋण के आधार पर 10,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने के लिए 21-9-1982 को नेपाल सरकार के साथ